



8.3.83

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301]

No. 301]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, जुलाई 7, 1983/आषाढ़ 16, 1905

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 1983/ASADHA 16, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 7 जुलाई 1983

का०आ० 497(अ).—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 387 (अ) तारीख 7 जुलाई, 1979, सं० का० आ० 497(अ) तारीख 5 जुलाई, 1980, सं० का० आ० 541 (अ) तारीख 6 जुलाई, 1981 और सं० का० आ० 480(अ) तारीख 7 जुलाई, 1982 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 426(अ) तारीख 8 जुलाई, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स एसोसिएटेड इन्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर नामक औद्योगिक उपक्रम के रसायन एकक का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की

उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 7 जुलाई, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए ग्रहण कर लिया गया था और मैसर्स असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध मैसर्स असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पास एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 7 जुलाई, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[का० सं० 4(4)/80-सी०यू०एस०]

**MINISTRY OF INDUSTRY**  
**(Department of Industrial Development)**

**ORDERS**

New Delhi, the 7th July, 1983

**S.O. 497(E).**—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, No. S.O. 426(E), dated the 8th July, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), read with the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 387(E) dated the 7th July, 1979, No. S.O. 497(E), dated the 5th July, 1980, No. S.O. 541(E), dated the 6th July, 1981 and No. S.O. 480(E), dated the 7th July, 1982, the management of the chemical unit of the industrial undertaking known as Messrs Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) upto and inclusive of the 7th July, 1983, and Messrs Assam Industrial Development Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of Messrs Assam Industrial Development Corporation Limited or a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 7th July, 1984.

[No. 4(4)/80-Cus.]

**का० आ० 498(अ).**—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 426(अ) तारीख 8 जुलाई 1974 द्वारा, मैसर्स एसोसिएटेड इण्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर नामक औद्योगिक उपक्रम के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) रसायन एकक का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 7 जुलाई, 1979 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था;

और उक्त आदेश की अवधि को 7 जुलाई, 1984 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबंध में अनुसूचित उद्योग, अर्थात्

रसायन उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरणपत्रों, करारों, परिनिर्धारणों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जो उनसे भिन्न है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित है), जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कंपनी पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कंपनी को लागू हैं, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पहले उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

[फा० सं० 4(4)/80-सी०यू०एस०]

ए० पी० सरवान, संयुक्त सचिव

**S.O. 498(E).**—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 426(E), dated the 8th July, 1974, the management of the chemical unit of the industrial undertaking known as Messrs Associated Industries (Assam) Ltd., Chandrapur (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of the 7th July, 1979;

And whereas the duration of the said order was extended from time to time up to and inclusive of the 7th July, 1984;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the chemical industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. 4(4)/80-Cus.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.